अपराह्न 3.16 बजे

प्रधानमंत्री द्वारा वक्तव्य

इटली, फ्रांस और मिस्र की हाल की यात्रा

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (डॉ. मनमोहन सिंह): अध्यक्ष महोदया, आज सुबह मैं अपनी फ्रांस और मिस्र की यात्रा से वापिस आया। उसके पूर्व मैं जी-8 और जी-5 की बैठकों के लिए इटली गया था।

जी-8 और जी-5 देशों की बैठक एक सालाना आयोजन हो गई है। इस साल की बैठकों का एजेंडा व्यापक था परंतु उसका मुख्य फोकस वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मंदी के ऊपर था।

वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट से विकासशील देश सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। मैंने प्रणालीगत असफलताओं को दूर करने के लिए और विश्व अर्थव्यवस्था को तेज करने के लिए सभी देशों द्वारा एक साथ और समन्वित कार्रवाई किए जाने के महत्व पर जोर दिया। इस समय यह जरूरत है कि विकासशील देशों की ओर पर्याप्त पूंजी प्रवाह बनाए रखा जाए और बाजारों की गतिविधियों में रोक न आने दी जाए।

विश्व समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में मैंने जी-8 और जी-5 देशों को अवगत करा दिया कि इस पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के अपने दायित्व को पहचानते हैं, परंतु जलवायु परिवर्तन की समस्या विकासशील देशों में गरीबी बनाए रखते हुए दूर नहीं की जा सकती। मैंने जलवायु परिवर्तन पर भारत की कार्य योजना के बारे में, और जी-8 राष्ट्रीय मिशन हमने इस संबंध में बनाए हैं उनके बारे में, अन्य देशों को बताया। हम इस विषय पर और भी कार्रवाई करने को तैयार हैं बशर्ते विकसित देशों से विकासशील देशों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और नई टेक्नोलॉजी प्राप्त होने के लिए विश्वसनीय व्यवस्था की जाए।

फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में भारत का एक सम्मानित अतिथि के रूप में शामिल होना हम सबके लिए सम्मान और गर्व की बात है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के बहादुर जवानों को फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस परेड में नेतृत्व करते हुए देखकर मुझे कितने गर्व का अनुभव हुआ। फ्रांस के साथ हमारी सामरिक भागीदारी है। इसी भावना में राष्ट्रपति सरकोजी के साथ हुए विचार विमर्श में हम दोनों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग के पूरे दायरे की समीक्षा की जिसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। राष्ट्रपति सरकोजी ने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि फ्रांस भारत के साथ पूरे नागरिक परमाणु सहयोग के लिए तैयार है।

मिस्र में मैंने निर्गुट सम्मेलन के 15वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। एन.ए.एम. दुनिया के लगभग दो तिहाई देशों की सशक्त आवाज है। मुझे पंडित नेहरू जी का कथन याद आया जिसमें उन्होंने एन.ए.एम. को विश्व मामलों में एक नैतिक ताकत कहा था। शिखर बैठक में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं, में निर्णय लेने की प्रक्रिया को वास्तविकता के अनुरूप बनाए जाने का आह्वान किया गया। मुझे खुशी है कि हमारे दृष्टिकोण को शिखर बैठक में व्यापक समर्थन मिला और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निंदा करने के हमारे आह्वान को माना गया।

इस सम्मेलन के दौरान मैंने मिस्र, श्रीलंका, वियतनाम और फिलीस्तीन के राष्ट्राध्यक्षों तथा बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात की। मैंने पाया कि ये सभी देश एक स्वर से भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में हमने भारत-पाक संबंधों की वर्तमान स्थिति, इसकी भावी संभावनाओं और इन संभावनाओं का एहसास करने के लिए जरूरी कदमों पर चर्चा की।

मैंने उन्हें आतंकवाद के मसले, खासकर मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों पर भारत के लोगों की तीव्र भावनाओं से अवगत कराया। हम इन हमलों के बारे में पाकिस्तान द्वारा हमें दिए गए जांच के कागजातों की समीक्षा कर रहे हैं। मैंने प्रधानमंत्री श्री गिलानी को इस बात से भी अवगत कराया कि केवल मुंबई हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ सतत, प्रभावशाली और विश्वसनीय न्यायिक कार्रवाई करने से काम नहीं चलेगा बल्कि पाकिस्तान को आतंकवादी गुटों की सभी गतिविधियों पर लगाम लगानी होगी ताकि भविष्य में ऐसे हमले न हों।

हमारा हमेशा यह मानना रहा है कि पाकिस्तान के

[डॉ. मनमोहन सिंह]

साथ सार्थक वार्ता तभी हो सकती है जब वे भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल न होने दें।

प्रधानमंत्री श्री गिलानी ने मुझे इस बात का भरोसा दिलाया कि पाकिस्तान मुंबई हमलों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि इन आतंकवादी गुटों की गतिविधियों के खिलाफ पाकिस्तान में आम सहमति है और इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जा रही है। यही पाकिस्तान के भी हित में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री गिलानी के साथ गए विभिन्न पार्टियों के माननीय सांसदों ने भी मुझे यह बताया कि पाकिस्तान में इस मुद्दे पर राजनैतिक सहमति है।

संयुक्त बयान के अनुसार आतंकवाद पर कार्रवाई को समग्र वार्ता प्रक्रिया के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और इस कारण ऐसी कार्रवाई करने के लिए हम और मुद्दों पर प्रगति का इंतजार नहीं कर सकते। इससे विकास के अन्य मुद्दों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमलों के खतरों का मुकाबला करने के लिए समय पर सार्थक और विश्वसनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे।

हम पाकिस्तान के साथ कब और कितनी व्यापक बातचीत करेंगे यह इस बात पर निर्भर होगा कि दोनों देशों के संबंधों में कितनी प्रगति हुई है। फिलहाल, हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के विदेश सचिव जरूरत के मुताबिक बार-बार मिलेंगे और अपने-अपने विदेश-मंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान मिलेंगे।

महोदया, जैसा कि मैंने इस सभा में पहले भी कहा है कि भारत, पाकिस्तान के साथ सहयोगपूर्ण संबंध चाहता है। एक स्थिर, समृद्धशाली दक्षिण एशिया, जिसमें अमन, शांति और सद्भावना हो, का सपना साकार करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हम आधे रास्ते से भी आगे जाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि पाकिस्तान एक सार्थक वार्ता का माहौल बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी महीनों में इस दिशा में सकारात्मक हालात पैदा होंगे।

महोदया मैं इस भरोसे के साथ स्वदेश लौटा हूं कि विश्व के नेताओं के साथ मेरी बातचीत से भारत के हित आगे बढ़ेंगे।

[ग्रंथालय में रखा गया, *देखिए* एल.टी. संख्या 34815/09]

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा)**:** अध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो बात मैंने सुबह कही थी,...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदया: कृपया आप शांत रहें।

...(*व्यवधान*)

श्रीमती सुषमा स्वराज: ...(*व्यवधान*) जो बात सुबह मैंने कही थी, उसे प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)**:** पाकिस्तान की यह काफी लंबे समय से मांग थी कि आतंकवाद को वार्ता के साथ न जोड़ा जाए और हमने इसे मान लिया है। इसके लिए सात माह क्यों लिए जाएं? यह सिर्फ मुम्बई के कारण है कि आपने इसे रोक दिया और भारत ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाया। ऐसा क्या हुआ कि आपने इसे बदल दिया? हमें यह समझ में नहीं आया ...(*व्यवधान*)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब प्रधानमंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो स्पष्टीकरण मांगने की पद्धति नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो हम एक व्यवस्थित चर्चा कर सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इस सभा में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि वक्तव्य के उपरांत स्पष्टीकरण चाहा जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन हम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हम स्ट्रक्चर्ड वाद-विवाद करेंगे। परन्तु इस मुद्दे पर सरकार के झुकने पर विरोध स्वरूप मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी बहिर्गमन करे...(*व्यवधान*)